

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय महाविद्यालय, बनवसा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-293/xxiv(7)/2016-13(2)/16 दिनांक 20.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय महाविद्यालय, बनवसा के भवन निर्माण कार्यों हेतु अनुमोदित रू० 368.87 लाख की धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू० 318.87 लाख की धनराशि के विरुद्ध रू० 100.00 लाख (रू० एक करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिता निधि से स्वीकृत करते हुए व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-06 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, बनवसा के भवन निर्माण कार्यों हेतु रू० 100.00 लाख (रू० एक करोड़ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है।

2- उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश-490 xxvii-1/2016 दिनांक 31.03.2016, में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

5- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

6- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम तल व भूतल की एक साथ DPR प्रस्तुत की गयी जिसे TAC द्वारा परीक्षणोपरान्त रू० 576.70 लाख का औचित्यपूर्ण पाया गया। तत्पश्चात् प्रथम तल की DPR उपलब्ध करायी गयी जिसे TAC ने रू० 260.30 लाख औचित्यपूर्ण माना। चूंकि उपरोक्त स्वीकृति भूतल जिसकी लागत रू० 368.87 लाख है, के सापेक्ष रू० 50.00 लाख की दी जा रही है। जिसकी DPR कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुये 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था से DPR प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

- i- आगणन में रू0 5.6 प्रतिशत सेवा कर देय नहीं होगा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-9/2016 दिनांक 01 मार्च, 2016 द्वारा सिविल कार्यों पर सेवा कर को 31 मार्च, 2020 तक Exempt कर दिया गया है।
 - ii- Labour Cess (01 प्रतिशत) अनुमन्य नहीं है, क्योंकि यह Overhead Charges में शामिल है।
 - iii- डीएसआर के अनुसार रुपये 01 करोड़ से अधिक के कार्यों पर मात्र तीन प्रतिशत कंटीजेंसी अनुमन्य है।
 - iv- बिल्डिंग तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का स्ट्रक्चरल एवं कन्सट्रक्शन ड्रॉइंग संलग्न किया जाय, जिससे विभिन्न सामग्रियों की अनुमन्यता का आंकलन किया जा सके।
 - v- Steel Reinforcement का प्राविधान Bar Bending Schedule के अनुसार किया जाय।
 - vi- आरसीसी ग्रेड DSR के मानकों के अनुसार N-25 रखा जाय।
 - vii- Normal Mix कंक्रीट के स्थान पर डिजाइन मिक्स कंक्रीट का प्राविधान किया जाय।
 - viii- Ceiling Plaster अनुमन्य नहीं है क्योंकि यह आर0सी0सी0 के आइटम रेट में सम्मिलित है।
 - ix- Non -schedule Items की दरें DGS&D या Manufacturer या कम से कम तीन कम्पनियों के ऑथोराइज्ड डीलर से कोटेशन प्राप्त कर लिया जाय।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग करके व्यय विवरण शासन एवं वित्त विभाग को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- 9- कार्य करने से पूर्व औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 10- निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का कड़ाई से पालन किया जाय।
- 11- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- 12- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 13- तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।
- 14- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 15- उक्त कार्यों हेतु राज्य आकस्मिता निधि से स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा यथासमय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव।